(7) *Biecco Lawrie Ltd:*

On account of implementation of revival package the company has turned around and BIFR have declared the company no longer sick.

(8) *Vigyan Industries Ltd:*

The BIFR has approved a comprehensive revival package covering financial restructuring, capital expenditure and various other reliefs and concessions which are in operation. As a result the company earned profit during 1994-95.

(9) *Bharat Brakes & Valves Ltd:*

The revival scheme approved by BIFR in January, 1995 for implementation was without the consent of Government. The Group of Ministers considered the revival scheme and found that operating agency report is were liberal. BIFR has been requested to modify the sanctioned scheme and BIFR have decided to sanction fresh scheme. The fresh/revised sanction is obtained.

(10) & (11) *Bharat Pumps Compressors Ltd. and Triveni Structurals Ltd:*

The sanctioned scheme for these companies requires released of funds, financial restructuring and provisions of counter guarantee to SBI for providing banking facility for implementation of the revival scheme. Plan & non-plan funds as per immediate requirement of the companies have been released. The financial restruct ring and provisions of counter guarantee to SBI is under active consideration of the Govt.

(12) *Braithwaite & Co. Ltd.:*

The sanctioned scheme of the company has been received recently and action is being taken for restructuring and release of funds.

ग्रामीण लोगों को रोजगार

1060. **श्री रामजीलाल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांवों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है और जिला विकास ग्रामीण अभिकरण द्वारा इस राशि को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) यह सत्य नहीं है कि गांवों में बेरोजगार लोगों को विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल रहा है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना, मंत्रालय द्वारा गांवों में बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही दो प्रमुख मजदूरी रोजगार योजनाएं है। गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण विवरण-I और II में है। **(नीचे देखिए)**

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्र द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 3862.00 करोड़ रुपए तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1570.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिलों के लिए रिलीज की गई निधियों में से संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/जिला परिषदों द्वारा इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के निर्धारित क्षेत्रों के लिए निधियां मुहैया कराने के उपरांत पंचायतों को 80 प्रतिशत निधियां रिलीज की जानी होती है। सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यों को जिला स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिनों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95 (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	677.93	1028.90	812.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.52	4.85	5.58
3.	असम	109.72	278.24	263.29
4.	बिहार	1036.16	1474.25	986.88
5.	गोआ	8.12	8.53	6.45
6.	गुजरात	235.03	202.64	258.48
7.	हरियाणा	32.63	33.29	33.96
8.	हिमाचल प्रदेश	26.16	34.54	28.87
9.	जम्मू और कश्मीर	43.01	32.16	88.04
10.	कर्नाटक	418.29	651.30	499.67
11.	केरल	134.54	120.43	101.01
12.	मध्य प्रदेश	709.66	849.24	1075.25
13.	महाराष्ट्र	823.53	1188.50	1100.73
14.	मणिपुर	5.23	6.68	7.16
15.	मेघालय	8.90	9.55	8.50
16.	मिजोरम	4.78	6.32	5.72
17.	नागालैण्ड	15.47	16.02	8.47
18.	उड़ीसा	326.39	522.96	604.51
19.	पंजाब	31.78	38.57	24.36
20.	राजस्थान	339.09	450.37	545.58
21.	सिक्किम	13.42	10.14	7.03
22.	तमिलनाडु	767.86	881.10	1027.66
23.	त्रिपुरा	13.94	23.41	29.02
24.	उत्तर प्रदेश	1496.29	1791.16	1395.94
25.	पश्चिम बंगाल	525.55	554.03	580.82
26.	अंडमान निकोबार	1.71	1.81	2.59
27.	दादर व नगर हवेली	2.70	2.34	2.07
28.	दमन व द्वीप	0.12	0.59	0.55
29.	लक्षद्वीप	2.68	2.21	1.91
30.	पांडिचेरी	3.81	4.27	4.72
	कुल:	7821.02	10258.40	9517.07

विवरण-II

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिनों की संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	62.42	277.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.64	20.84
3.	असम	31.75	95.50
4.	बिहार	31.44	193.72
5.	गुजरात	6.75	35.26
6.	हरियाणा	15.20	34.64
7.	हिमाचल प्रदेश	0.05	3.20
8.	जम्मू व कश्मीर	3.46	59.85
9.	कर्नाटक	32.12	177.45
10.	केरल	2.60	27.64
11.	मध्य प्रदेश	51.26	363.78
12.	महाराष्ट्र	31.53	233.89
13.	मणिपुर	3.06	28.60
14.	मेघालय	शून्य	1.39
15.	मिजोरम	8.52	41.71
16.	नागालैण्ड	33.92	28.81
17.	उड़ीसा	31.43	281.24
18.	राजस्थान	50.00	273.11
19.	सिक्किम	0.82	8.50
20.	तमिलनाडु	10.96	141.29
21.	त्रिपुरा	16.14	60.35
22.	उत्तर प्रदेश	15.00	165.63
23.	पश्चिम बंगाल	52.53	184.79
24.	अंडमान निकोबार	0.10	0.57
25.	दादर व नगर हवेली	0.04	0.10
26.	दमन व द्वीप	शून्य	0.13
27.	लक्षद्वीप	शून्य	0.34
	कुलः	494.74	2739.5

टिप्पणी—सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरू की गई थी।